उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन में निवेश हेतु तैयार

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, **उत्तर प्रदेश सरकार** नागरिक उड्डयन क्षेत्र में **2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (16,000 करोड़ रुपए से अधिक) के निजी निवेश** का लक्ष्य बना रही है।

- विमानन प्रशिक्षण, विमान रखरखाव और एयरो-स्पोर्ट्स जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा, प्रस्तावित निवेश का उपयोग **मौजूदा हवाई पट्टियों को विकसित तथा उन्नत करने** के लिये किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के तहत, तत्काल विकास के लिये चिह्नित 14 सरकारी हवाई पट्टियों के अलावा, राज्य **225 मार्गों को चालू करने के लिये** कदम उठा रहा है।
  - छह हवाई पट्टियों अर्थात् **अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद और सोनभद्र** को RCS के तहत उड़ानों को संभालने के लिये उन्नत किया जा रहा है।
  - राज्य ने हवाई पट्टियों के आधुनिकीकरण, भूमि अधिग्रहण और अन्य के लिये **नागरिक उड्डयन बुनियादी ढाँचे** हेतु चालू वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में लगभग **28,000 करोड़ रुपए का बजट** आवंटित किया है।
- उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 24 में **यात्रियों की संख्या में 20% की वृद्धि देखी गई,** जो अवकाश और व्यावसायिक पर्यटन में विमानन विकास में तीव्र वृद्धि का संकेत है।
  - रकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थलों में हेलीकॉप्टर टैक्सियों को भी बढ़ावा दे रही है।
  - वर्ष 2023 में, UP टूरिज़्म ने आगरा और मथुरा के बीच 30 वर्षों के लिये हेलीपोर्ट संचालित करने हेतु राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- **UP सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, वर्ष** 2023 में पर्यटकों की आमद में 50% की वृद्धि दर्ज करते हुए 480 मिलियन तक पहुँच गया है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना

- **परिचय:**
  - क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास तथा **क्षेत्रीय संपर्क** बढ़ाने के लिये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को लॉन्च किया गया था।
  - यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (National Civil Aviation Policy), 2016 का हिस्सा है।
  - यह योजना **10 वर्ष की अवधि** के लिये लागू है।
- **उद्देश्य:**
  - भारत के सुदूर क्षेत्रों और क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना।
  - दूरस्थ क्षेत्रों का विकास और व्यापार एवं वाणिज्य तथा पर्यटन विस्तार को बढ़ाना।
  - आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना।
  - विमानन क्षेत्र में रोज़गार सृजन।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - इस योजना के तहत एयरलाइंस को कुल सीटों की 50% सीटों के लिये हवाई किराया 2,500 रुपए प्रति घंटे की उड़ान पर सीमित करना होगा।
  - इस उद्देश्य को निम्नलिखित के आधार पर प्राप्त किया जाएगा
    - केंद्र एवं राज्य सरकारों और हवाई अड्डों के संचालकों की ओर से रियायतों के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से।
    - वयवहार्यता अंतराल अनुदान (Viability Gap Funding- VGF)- संचालन की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर को कम करने के लिये एयरलाइंस को प्रदान किये जाने वाले सरकारी अनुदान के माध्यम से।
      - योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अनुदान (Regional Connectivity Fund- RCF) प्रदान किया गया है।

- इस निविश में सहभागी राज्य सरकारें (केंद्रशासति प्रदेश और NER राज्यों के अतिरिक्त जिनका योगदान 10% है) 20% की भागीदारी करेंगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-set-to-invest-in-civil-aviation